वस्त्र मंत्रालय

केबिनेट के लिए दिसम्बर, 2018 माह का मासिक सारांश

1. नीतिगत निर्णय तथा महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ :

i. हैंडलूम क्षेत्र :

(क) एमएसएमई सहयोग व आउटरीच कार्यक्रम के अधीन 12 चिन्हित जिलों में सम्बद्ध बुनकर केंद्रों के साथ मिलजुलकर विविध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। जैसे कि 2 नवम्बर 2018 से कार्यक्रम के आरंभ से लेकर 31 दिसम्बर 2018 तक 16958 बुनकरों के पहचान कार्ड, 6505 कौशल उन्नयन/ वर्कशेड/करघों लाइटिंग इकाइयों, 10339 के लिए यार्न पासबुक, 4018 मुद्रा लोन तथा 6371 के लिए सामाजिक सुरक्षा (बीमा) का नामांकन किया जा चुका है। इसके अलावा, हैंडलूम मार्क/इंडिया हैंडलूम ब्रांड के लिए 93 पंजीकरण किए जा चुके हैं तथा इनके 16460 लेबल जारी किए गए। 2959 बुनकरों ने विपणन कार्यक्रमों में भाग लिया तथा 98.92 लाख रु मूल्य की बिक्री की गई।

(ख) छः राष्ट्र स्तरीय तथा दो राज्य स्तरीय हैंडलूम एक्स्पो/विपणन कार्यक्रमों को दिसम्बर 2018 में दिल्ली, लखनऊ, जम्मू, कोलकाता, चेन्नई, पुणे तथा हैदराबाद में आयोजित किया गया जिसने उपभोक्ता तथा हथकरघा बुनकरों के बीच प्रत्यक्ष बाजार अंतर्संपक उपलब्ध कराए।

ii. रेशम क्षेत्र :

(क) माननीय वस्त्र राज्य मंत्री ने रेशम 22 दिसम्बर 2018 को लखनऊ में आयोजित"रेशम समग्र कार्यशाला" तथा पं. दीन दयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता अवार्ड कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से चुने गए रेशम उत्पादकों को सम्मानित किया। केन्द्रीय रेशम बोर्ड(सीएसबी)/भारतीय सिल्क मार्क संगठन(एसएमओआई), वाराणसी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

(ख) भारतीय सिल्क मार्क संगठन (एसएमओआई), नई दिल्ली ने भारत व इण्डोनेशिया के बीच डिजाइन के तालमेल की संभावनाओं को ढूंढने तथा गतिशीलविश्वव्यापी बाजारों की मांग को पूरा करने हेतु नये उन्नत डिजाइन तथा संरचनाओं को विकसित करने के लिए"आईएमखादी"फाउंडेशन द्वारा इण्डोनेशिया दूतावास, नई दिल्ली में "विश्वव्यापी होती खादी-बाटिक बुनाई" पर आयोजित व्यापार एन्कलेव/कार्यशाला में भाग लिया।

iii. कपास: दिसम्बर, 2018 के माह के दौरान कपास बीज (कपास) का संपूर्ण भारत से आगम 71.23 लाख गाँठें था। इसमें से, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कार्यप्रणाली

के अंतर्गत 1.60 लाख कपास बीज की गाँठें भारतीय कपास निगम द्वारा अधिप्राप्त की गई।

iv. **<u>पावरलूम सेक्टर</u>:** दिसम्बर 2018 के दौरान पावरलूम कार्मिकों के लिए सामूहिक बीमा योजना के अधीन 4,01,432 रु के प्रीमियम के भारत सरकार के कुल भाग के साथ विविध नोडल एजेंसियों द्वारा 2,444 पावरलूम कार्मिकों का योजना के अंतर्गत नामांकन किया गया।

v. **तकनीकी उन्नयन :** दिसम्बर 2018 के माह के दौरान 412.33 करोड़ रु की परियोजना लागत तथा संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन फंड योजना (ए-टीयूएफएस) के अधीन 36.37करोड़ रु की सब्सिडी आवश्यकता के साथ 144 यूआईडी जारी किए गए।